प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री रामलाल, निवासी जनपद-चित्रकूट की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024) दिनांक-07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री रामलाल, किहुनिया, थाना-मारकुडी, जनपद-चित्रकूट का निवासी है। डकैती व लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक-09/10.09.1979 की रात्रि को बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमन्चों व कुल्हाड़ी से मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा शवों को रस्सी से बांधकर गंगा के तेज बहाव में फेंक दिया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-317/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 395, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, फतेहपुर के आदेश दिनांक 09.07.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.01.2001 द्वारा निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को परिवर्तित करते हुये दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.12.2009 द्वारा दोषमुक्त को परिवर्तित करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 20.03.2024 तक 14 वर्ष, 18 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 08 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई की जाती है तो पुनः गम्भीर घटना घटित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है बन्दी को जेल मे आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में डकैती व लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक-09/10.09.1979 की रात्रि को बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमन्चों व कुल्हाड़ी से मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा शवों को रस्सी से बांधकर गंगा के तेज बहाव में फेंक दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुन्ना पुत्र रामलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना (बन्दी संख्या-382/2019) पुत्र श्री रामलाल, निवासी जनपद-चित्रकूट के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-752/2025/136(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-752/2025/136/22-2-2025-17(144)/2025

दिनांक 03 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री रामलाल, किहुनिया, थाना-मारकुडी, जनपद-चित्रकूट का निवासी है। डकैती व लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक-09/10.09.1979 की रात्रि को बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमन्चों व कुल्हाड़ी से मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा शवों को रस्सी से बांधकर गंगा के तेज बहाव में फेंक दिया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-317/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 395, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, फतेहपुर के आदेश दिनांक 09.07.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.01.2001 द्वारा निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को परिवर्तित करते हुये दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.12.2009 द्वारा दोषमुक्त को परिवर्तित करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 20.03.2024 तक 14 वर्ष, 18 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 08 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई की जाती है तो पुनः गम्भीर घटना घटित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है बन्दी को जेल मे आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में डकैती व लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक-09/10.09.1979 की रात्रि को बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमन्चों व कुल्हाड़ी से मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा शवों को रस्सी से बांधकर गंगा के तेज बहाव में फेंक दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुन्ना पुत्र रामलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in